स्थानीय सरकार से बेहतर तालमेल के लिए क्षमता निर्माण

चर्चा का मुख्य मुद्दा

स्थानीय सरकार के साथ बेहतर ताल-मेल बनाने के लिए संस्थाओं को क्या कौशल और क्षमता निर्माण करने की ज़रूरत है? सभी वक्ताओं ने चुनौतियों के साथ ही आगे के बदलाव पर चर्चा की, जिससे जागरूकता से एक्शन तक की दूरी पूरी की जा सके।

यह नोट 23 दिसम्बर 2020 को एकाउंटेबिलिटी इनिशिएटिव द्वारा आयोजित 'बढ़ते कदम' वेबिनार में हुई चर्चा पे आधारित है।

सबसे पहले, सेवा मंदिर के रौनक शाह ने संस्थाओं की तरफ से सरकार से जुड़ने में आने वाली समस्याओं पर बात की।

> सरकार के ढांचे को समझना, यह समझना के कौनसे स्तर पर कौन क्या काम कर सकता है और विकेन्द्रीकृत निर्णय कहाँ पर लिए जाते है जानना ज़रूरी है। तभी इस जटिल सिस्टम को समझ कर आगे का काम किया जा सकता है।

- उनका कहना था कि सरकार और संस्थाओं के बीच तालमेल और संवाद के मौके पिछले 20 साल से कम हो गए हैं।
- साथ ही, हमेशा से राजनैतिक शास्त्र की बातों को किताबी बातों के रूप में देखा गया है , जिसका असली जीवन में कोई महत्त्व नहीं है। ऐसे में, सरकार से जुड़ने और समझने में रूचि ज़्यादा नहीं पायी जाती है।
- यह ज़रूरी है कि संस्थाएं सिर्फ माँगे लेकर सरकार के पास ना जाए, लेकिन उनको समझने की कोशिश करें, ताकि दोनों तरफ से विश्वास का रिश्ता बन सके।
- उन्होंने कहा कि संस्थाओं के मन में सरकार के बारे में एक डर रहता है और इस डर से आगे बढ़कर अपनी बात रखना और रिश्ता बनाना ज़रूरी है। आम नज़रिया जो सरकार से दूर रहना का होता है, उससे आगे आना होगा।
- जानकारी का अभाव भी एक समस्या है। वह कहते हैं कि सरकार के ढांचे को समझना, यह समझना के कौन से स्तर पर कौन क्या काम कर सकता है और विकेन्द्रीकृत निर्णय कहाँ पर लिए जाते है, जानना ज़रूरी है। तभी इस जटिल सिस्टम को समझ कर आगे का काम किया जा सकता है।
- सरकार के अंदर का अपना काम करने का तरीका है और यह काफी जटिल और लम्बा हो सकता है। इसको समझना ज़रूरी है।
- विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के बारे में जानना खास तौर पर ज़रूरी है क्योंकि लोकल समस्याओं के समाधान भी लोकल या क्षेत्रीय स्तर पर सबसे बेहतर निकल सकेंगे।

इसके बाद, प्रथम से संजय कुमार ने भी सरकार के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किये।

> आज कल काफी जानकारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाती है और यह मान लिया जाता है कि सिस्टम में पारदर्शिता है। लेकिन कई बार आप पास जाकर देखेंगे तो जिन लोगों की सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है, वही निर्णय में शामिल नहीं किये जाते ।

- जागरूकता की बड़ी भूमिका है। आपको जानना होगा कि कौन-कौन सी योजनाएं है और उनके क्या-क्या लाभ कौन-कौन उठा सकते है। यही नहीं, यह भी जानना कई बार ज़रूरी होता कि इस लाभ को पाने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, यानि कौन से ऑफिस या अफसर के पास जाना है और कौन सा फॉर्म लेकर।
- हमने कोरोना वायरस लोकडाउन में ऐसी जागरूकता की मदद से लगभग 100 से ज़्यादा साथियों को राशन कार्ड के लाभ से जोड़ने का काम भी किया।
- ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानि जी.पी.डी.पी के बारे में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि पंचायत के लोगों (जैसे सरपंच) से रिश्ता बनाना ज़रूरी है।
- अगर अगले साल का प्लान बनाया जा रहा है,तो पंचायत के लोगों के साथ संस्थाओं का ऐसा संवाद होना चाहिए, कि क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा करके एक रणनीति तैयार की जा सके।
- उन्होंने कहा कि आज कल काफी जानकारी वेबसाइट पे देखने को मिल जाती है, और यह मान लिया जाता है कि सिस्टम में पारदर्शिता है। लेकिन कई बार आप पास जाकर देखेंगे तो जिन लोगों की सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है, वही निर्णय में शामिल नहीं किये जाते ।
- उन्होंने यह भी कहा कि बदलाव और विकास के बीच संतुलन बनाये रखना ज़रूरी हैं । कई बार सरकार बदलने की वजह से विकास कामों में निरंतरता नहीं आ पाती है।

आई.ए.इस अफसर पी.आनंदी ने सरकार और संस्थाओं के रिश्ते को सरकार के नज़रिये से देखते हुए अपनी बात आगे रखी।

> हर सरकार की भी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। संस्थाओं को कोशिश करनी चाहिए कि सरकार के साथ बात करके ऐसे कुछ काम ढूंढ निकाले जो वह तो करना चाहते ही हैं, लेकिन वो सरकार के लिए भी प्राथमिकता रखते हो।

- उन्होंने कहा कि समस्याएं दोनों तरफ है, और उन्होंने रौनक शाह जी की बात से सहमत होते हुए कहा कि पहले के मुकाबले अब सरकार और संस्थाओं को साथ लाने के औपचारिक मौके कम हो गए हैं।
- ऐसे में अफसरों को एक व्यक्तिगत स्तर पर संस्थाओं के साथ पार्टनरशिप करने का प्रयास करना होता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अधिकारी भी बहुत संभल कर चलना चाहते हैं। यह इसलिए क्योंकि संस्थाएं बहुत हैं और काम भी अच्छा करती हैं, लेकिन कई बार उनके बारे में पता नहीं होता। जानकारी का अभाव दोनों तरफ से होता है।
- क्योंकि कोई औपचारिक माध्यम नहीं है, ऐसे अधिकारी जो संस्थाओं से जुड़ने में रूचि रखते हैं, उन्हें संभल कर चलना होता है। जानकारी की अभाव की तरह ही, डर भी दोनों तरफ से है। अधिकारियों को इस बात का डर है कि कहीं किसी ऐसी संस्था से जुड़ गए जिसके बारे में वह ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और नाम खराब ना हो जाए है।
- उन्होंने कहा कि हर सरकार की भी कुछ प्राथमिकताएं होती हैं। संस्थाओं को कोशिश करनी चाहिए कि सरकार के साथ बात करके ऐसे कुछ काम ढूंढ निकाले जो वह तो करना चाहते ही हैं, लेकिन वो सरकार के लिए भी प्राथमिकता रखते हो।
- कई बार संस्थाओं के लोग सरकार के लम्बे और जटिल सिस्टम से परेशान हो जाते हैं। यह समझना ज़रूरी है कि एक हद के बाद अधिकारी के हाथ बंधे हुए होते हैं, और वह सिर्फ आपको टालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं।
- ऐसे में जानकार होना और सिस्टम को समझना फायदेमंद है। कई बार अगर आप यह जानते हैं कि आपका कोई काम पंचायत स्तर से होकर ब्लॉक लेवल पर अटका है, तो आप वहाँ जाकर अपने काम को जल्दी भी करवा सकते हैं।
- बदलाव और विकास की बात करते हुए उन्होंने कहा कि निरंतरता सरकार और जनता दोनों पर निर्भर हैं ।